मैसूर विश्वविद्यालय और अन्य

बनाम

सी.डी. गाविंदा राव और अन्य

1963

(पी.बी. गजेंद्रगढ़कर, के. सुब्बा राव, के. एन. बांचू, एन. राजगोपाल अयंगर और जे. आर. मधोलकर, जे.जे.)

"रिट क्यू वारंटो, मैसूर विश्वविद्यालय संविधान के प्रथम नियुक्ति बोर्ड द्वारा रीडर की नियुक्ति का दायरा, अनुछेद 226, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार

मैसूर विश्वविद्यालय, अपीलकर्ता नं. 1 द्वारा प्रोफेसरों के 6 पदों और रीडर्स के 6 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापित किया गया। इनमें अंग्रेजी के प्रोफेसर और अंग्रेजी के रीडर का पद भी शामिल था। रीडर के पद के लिए उम्मीदवारों के पास

(ए) विषय में किसी भारतीय विश्वविद्यालय से प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री होनी आवश्यक थी:

(बी) डॉक्टरेट मानक की शोध डिग्री या उच्च मानक का प्रकाशित कार्य और;

(सी) प्रोफेसरों के मामले में 10 साल और रीड़र के मामले में 5 साल तक स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाने का अनुभव। अन्निया गौड, अपीलकर्ता नं. 2, का चयन एक नियुक्ति बोर्ड द्वारा किया गया था जिसका गठन कई आवेदकों की फिटनेस की जांच करने के लिए किया गया था और उन्हें सेंट्रल कॉलेज, बैंगलोर में अंग्रेजी में रीडर नियुक्त किया गया था।

प्रतिवादी सी. डी. गोविंदा राव ने मैसूर उच्च न्यायालय में संविधान के अनुछेद 226 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें उन्होंने प्रार्थना भी की कि अपीलार्थी संख्या-1 को बुलाने एवं कारण दर्शाने हेतु अधिकार पृच्छा याचिका जारी की जाए कि किस अधिकारिता के अंतर्गत उनके द्वारा रीड़र की पोस्ट पर नियुक्ति प्राप्त की गई। उन्होंने अपीलार्थी संख्या-1 को उनकी रीड़र हेतु नियुक्ति बाबत परमादेश या अन्य उचित रिट या निर्देश के लिए भी प्रार्थना की। उनका तर्क था कि अन्निया गौड़ की नियुक्ति निर्धारित योग्यता अनुसार अवैध थी।

उच्च न्यायालय ने अन्निया गौड़ की नियुक्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया कि वह पहली योग्यता को पूरा नहीं करते थे जिसके लिए आवश्यक था कि "उनके पास भारतीय विश्वविद्यालय की प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री होनी चाहिए" क्योंकि उन्होंने केवल 50.2 अंक हासिल किए थे। प्रतिशत अंक जबकि द्वितीय श्रेणी के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत था। जहां तक दूसरी और तीसरी योग्यता का संबंध है, उच्च

न्यायालय ने अन्निया गौड़ के खिलाफ कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। अपीलार्थी विशेष अनुमति के माध्यम से इस अदालत समक्ष उपस्थित आए।

प्रतिपादित किया गया है कि:

(i) उच्च न्यायालय का निर्णय गलत था क्योंकि उच्च न्यायालय ने अन्निया गौड़ द्वारा प्राप्त डरहम विश्वविद्यालय की मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पर विचार नहीं किया। यह सच है कि अन्निया गौड़ के पास किसी भारतीय विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास एक विदेशी विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स की वैकल्पिक योग्यता थी। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता संख्या की नियुक्ति को रद्द करने के लिए यथाधिकार रिट जारी करने में गलती की थी।

(ii) नियुक्तियों के बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा नामित किए जाते हैं और जब उनके द्वारा की गई सिफारिशों और उनके आधार पर नियुक्तियों को अदालतों के समक्ष चुनौती दी जाती है तो आम तौर पर अदालतों को विशेषज्ञों की राय में हस्तक्षेप करने में धीमी गति रखनी चाहिए। जब तक कि उनके खिलाफ दुर्भावना के आरोप न हों। आम तौर पर, अदालतों के लिए अकादमिक मामलों का निर्णय उन विशेषज्ञों पर छोड़ना बुद्धिमानी और सुरक्षित है जो आम तौर पर अदालतों की तुलना में उन समस्याओं से अधिक परिचित होते हैं जिनका उन्हें सामना करना

पड़ता है। इस मामले में उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि क्या कुलाधिपति द्वारा की गई नियुक्ति ने किसी वैधानिक या बाध्यकारी नियम या अध्यादेश का उल्लंघन किया है और ऐसा करते समय, उच्च न्यायालय को विशेषज्ञों के बोर्ड द्वारा व्यक्त की गई राय व सिफारिशों के प्रति उचित सम्मान दिखाना चाहिए था जिन पर कुलाधिपति ने कार्रवाई की थी। उच्च न्यायालय को यह नहीं सोचना चाहिए था कि बोर्ड एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण की तरह कार्य कर रहा था, जो निर्णय के लिए उसके पास भेजे गए विवादों का निपटारा कर रहा था। इसमें ऐसे लागू परीक्षण नहीं होने चाहिए जो उत्प्रेषण रिट के मामले में लागू होते हैं।

यथा वारंटो का रिट न्यायपालिका को कार्यपालिका को कानून के विरुद्ध सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्तियाँ करने से नियंत्रित करने और एक नागरिक को सार्वजनिक कार्यालय से वंचित होने से बचाने का एक हथियार देता है, जिस पर उसका अधिकार है। ये कार्यवाहियाँ जनता को सार्वजनिक पद पर कब्जा करने वालों से, कार्यपालिका की मिलीभगत से या उसकी उदासीनता से बचाती हैं

इससे पहले कि कोई व्यक्ति प्रभावी रूप से अधिकार पृच्छा की रिट का दावा कर सके, उसे अदालत को संतुष्ट करना होगा कि विचाराधीन

कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है और कानूनी अधिकार के बिना एक सूदखोर के पास है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 417 और 418/1963

मैसूर उच्च न्यायालय, रिट याचिका संख्या 1197, 1960/1963 में के निर्णय और आदेश दिनांक 7 मार्च 1962 से

विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता की ओर से सी. के. दफ्तरी, भारत के अटॉर्नी- जनरल, बी. आर. एथिराजुलु नायडू, एस.एन. एंडली,

रामेश्वर नाथ और पी.एल. बोहरा (सी.ए. संख्या 417/68 में)।

C.A.No 418/63 में अपीलकर्ता के लिए बी. के. गोविंदराजुलु और आर. गोपालकृष्णन, एस. के. वेंकटरांगा अयंगर. जे. बी. दादाचनजी

उत्तरदाताओं के लिए ओ.सी. माथुर, रविंदर नारायण।

अगस्त, 26, 1963. न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

गजेंद्रगढ़कर, जे.

जिस याचिका से विशेष अनुमति द्वारा ये अपील उठी हैं, वह प्रतिवादी, सी. डी. द्वारा दायर की गई थी। गोविंदा राव द्वारा मैसूर उच्च

न्यायालय में संविधान के अनुछेद 226 के तहत उस याचिका द्वारा उन्होंने प्रार्थना की कि 3. अधिकार पृच्छा की रिट जारी की जाए, जिसमें अन्निया गौड़ को यह बताने के लिए कहा जाए कि वह किस अधिकार के तहत सेंट्रल कॉलेज, बैंगलोर में अंग्रेजी में रिसर्च रीडर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से उन्हें रुपये 500-25-800 के वेतनमान पर रिसर्च रीडर नियुक्त करने के लिए परमादेश या अन्य उचित रिट या निर्देश के लिए भी प्रार्थना की। उनका मामला यह था कि रिसर्च रीडर के पद पर अन्निया गौड़ की नियुक्ति निर्धारित योग्यता के बावजूद अवैध थी और वह उस पद पर नियुक्त होने के लिए योग्य थे। इसीलिए वह चाहते थे कि अन्निया गौड़ की नियुक्ति रद्द कर दी जाए और उन्होंने विश्वविद्यालय को उन्हें उस पद पर नियुक्त करने का निर्देश देने के लिए एक रिट मांगी। अपनी याचिका में उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय के रजिस्टार और अन्निया गौड़ को विपरीत पक्ष के रूप में शामिल किया।

मैसूर विश्वविद्यालय और अन्निया गौड़ ने प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे की वैधता पर विवाद किया। उन्होंने आग्रह किया कि अन्निया गौड़ को सही तरीके से रिसर्च रीडर नियुक्त किया गया था और प्रतिवादी द्वारा दिया गया यह तर्क कि उक्त नियुक्ति अमान्य थी, उचित नहीं था।

इन दलीलों पर, दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने तर्कों के संबंध में शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य पेश किए गए। उच्च न्यायालय ने माना है कि

अन्निया गौड़ की नियुक्ति अवैध थी और इसलिए उनकी नियुक्ति हेतु पारित किया गया मैसूर विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रद्द किया गया, जिसके पश्चात यह निर्देशित किया गया कि कुलाधिपति द्वारा की गई उनकी नियुक्ति भी रद्द हो। यूनिवर्सिटी को अलग रखा जाना चाहिए। हालांकि, उच्च न्यायालय ने विपरीत पक्ष को उक्त पद पर उसकी नियुक्ति का निर्देश देते हुए परमादेश की रिट देने से परहेज किया, क्योंकि उसका मानना था कि भले ही अनिया गांडा की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिवादी आवश्यक रूप से उस पद के हकदार हो, उच्च न्यायालय के अनुसार, उस प्रश्न पर विश्वविद्यालय और बोर्ड को नये सिरे से विचार करना पड़ सकता है।

इसके बाद, विश्वविद्यालय और अन्निया गौड़ ने इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए एक प्रमाण पत्र के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद विश्वविद्यालय और अन्निया गौड़ ने अलग-अलग आवेदनों द्वारा विशेष अनुमति के लिए इस न्यायालय का रुख किया, और उन्हें विशेष अनुमति दिए जाने पर, वे हमारे सामने दो वर्तमान अपीलें लाए हैं (सिविल अपील 417 और 63 में से 418)। इस फैसले में, हम विश्वविद्यालय और अन्निया गौड़ को क्रमशः अपीलकर्ता 1 और 2 के रूप में वर्णित करेंगे।

ऐसा प्रतीत होता है कि 31 जुलाई 1959 को अपीलकर्ता नंबर 1 ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें प्रोफेसर के छह पदों और रीडर के छह पदों के लिए आवेदन मांगे गए। इनमें अंग्रेजी के प्रोफेसर और अंग्रेजी के रीडर का पद भी शामिल था. इन निर्धारित पदों के लिए निर्धारित योग्यताएं महत्वपूर्ण हैं और इस स्तर पर उन्हें निर्धारित करना सुविधाजनक हैंः

"योग्यताएँ:

(ए) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से प्रथम या उच्च "द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री या संबंधित विषय में किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता;

(बी) डॉक्टरेट मानक की शोध डिग्री या उच्च मानक का प्रकाशित कार्य;

(सी) आमतौर पर स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने और प्रोफेसरों के मामले में शोध मार्गदर्शन करने का दस साल (किसी भी मामले में पांच साल से कम नहीं) का अनुभव और डिग्री कक्षाओं को पढ़ाने और मामले में स्वतंत्र शोध का कम से कम पांच साल का अनुभव रीड़र के मामलों में।

(डी) क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ का ज्ञान एक वांछनीय योग्यता माना जाता है। उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी

जिनके पास शिक्षण और शाेध के संगठन में अनुभव है और उन्होंने उन्नत शोध कार्य भी किया है। "

मैसूर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 23) की धारा 26(2) के अनुसार, जैसा कि उस समय था, एक नियुक्ति बोर्ड नामित किया गया था, जिसमें कुलपति और अंग्रेजी के दो विशेषज्ञ शामिल थे। ये विशेषज्ञ थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पी. ई. दस्तूर और मद्रास के प्रोफेसर एल. डी. मर्फी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपीलकर्ता संख्या 1 को दिए गए अनुदान के अनुसरण में प्रोफेसर और रीडर के पदों का विज्ञापन किया गया था। अंग्रेजी में प्रोफेसर और रीडर के पदों के लिए चार आवेदन प्राप्त हुए और इन आवेदकों का बोर्ड द्वारा 8 जून, 1960 को साक्षात्कार लिया गया।

बोर्ड को प्रोफेसर सी.डी. से परामर्श करने का लाभ मिला। नरसिम्हैया, प्राचार्य, महाराजा कॉलेज, मैसूर प्रोफेसर नरसिम्हैया द्वारा व्यक्त की गई राय को ध्यान में रखने के बाद, बोर्ड ने चार आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे की उनमें से कोई भी यू.जी.सी. ग्रेड 800-1,250 में प्रोफेसर नियुक्त होने के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त नहीं है। तदनुसार, बोर्ड ने निर्णय लिया कि उक्त पदों को फिलहाल रिक्त रखा जाए और पुनः विज्ञापित किया जाए। यू.जी.सी. के तहत ग्रेड 500-25-800 रीडर के पद

को भरने के संबंध में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता नंबर 2 सबसे उपयुक्त व्यक्ति था और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उसे उक्त यू.जी.सी. के तहत ग्रेड योजना अन्तर्गत रीडर नियुक्त किया जाए। इस रिपोर्ट को 3 अक्टूबर, 1960 को चांसलर द्वारा उचित समय पर अनुमोदित किया गया था, और रीडर के पद पर नियुक्त होने के बाद, अपीलकर्ता नंबर 2 ने 31 अक्टूबर, 1960 को कार्यभार ग्रहण किया। इस बीच, उनके कार्यभार संभालने से पहले ही उनके कार्यालय के

प्रतिवादी ने अपनी वर्तमान याचिका 15 अक्टूबर 1960 को दायर की थी. और उसने अपीलकर्ता नंबर 1 के खिलाफ पद भरने के लिए आगे बढ़ने से निषेधाज्ञा का दावा किया था, लेकिन चूंकि पूद पहले ही भरा जा चुका था, इसलिए उसने अपने दावे को संशोधित किया और अपीलकर्ता संख्या 2 के विरुद्ध अधिकार पृच्छा रिट की मांग की। इस प्रकार दोनों अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी के बीच मुख्य विवाद अंग्रेजी में रीडर के पद पर अपीलकर्ता संख्या 2 की नियुक्ति की वैधता के संबंध में था. और जैसा कि पहले ही अंकित किया जा चुका है, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की दलीलों को बरकरार रखा और अपीलकर्ता नंबर 2 की नियुक्ति को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय के निर्णय से यह संकेत नहीं मिलता है कि उच्च न्यायालय का ध्यान अधिकार वारंट की रिट की तकनीकी प्रकृति की ओर आकर्षित किया गया था. जिसका वर्तमान कार्यवाही में प्रतिवादी द्वारा दावा किया गया था, और जिन शर्तों एेसी कार्यवाही में इससे पहले भी कोई रिट जारी हो सके पूरा किया जाना था।

ऐसी कार्यवाही में.

जैसा कि हेल्सबरी ने देखा है"

"अधिकार वारंटो की प्रकृति में एक सूचना ने अधिकार वारंटो के अप्रचलित रिट की जगह ले ली है जो किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ़ है जिसने किसी कार्यालय, मताधिकार, या स्वतंत्रता पर दावा किया है या उसे हड़प लिया है, यह जांच करने के लिए कि उसने किस प्राधिकारी द्वारा अपने दावे का समर्थन किया है, ताकि कार्यालय या मताधिकार का अधिकार निर्धारित किया जा सकता है।"

मोटे तौर पर कहा गया है, यथा वारंटी कार्यवाही एक न्यायिक उपाय प्रदान करती है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, जो एक स्वतंत्र वास्तविक सार्वजनिक कार्यालय या मताधिकार या स्वतंत्रता रखता है, को यह दर्शाने के लिए कहा जाता है कि वह किस अधिकार में उन कार्यालय, मताधिकार या स्वतंत्रता रखता है, ताकि इस पर उसका स्वामित्व विधिवत

निर्धारित किया जा सकता है, और यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्यालय के धारक के पास कोई शीर्षक नहीं है, तो उसे न्यायिक आदेश द्वारा उस कार्यालय से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, यथा वारंटो की प्रक्रिया न्यायपालिका को कार्यपालिका को कानून के विरुद्ध सार्वजनिक पद पर नियुक्तियाँ करने से नियंत्रित करने और एक नागरिक को उस सार्वजनिक पद से वंचित होने से बचाने का हथियार देती है. जिस पर उसका अधिकार है।

ये कार्यवाहियाँ जनता को सार्वजनिक कार्यानिय पर कब्जा करने वालों से बचाने की भी प्रवृत्ति रखती हैं, जिन्हें या तो कार्यपानिका की मिलीभगत से या उसकी उदासीनता के कारण जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार, उक्त देखा जाएगा इससे पहले कि कोई व्यक्ति प्रभावी रूप से अधिकार पृच्छा की रिट का दावा कर सके।

उसे न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि विचाराधीन कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है और बिना कानूनी अधिकार के प्राप्त किया गया है जो कि जांच का कारण बनेगा कि क्या तथाकथित व्यक्ति की नियुक्ति विधि के अनुसार की गई है या नहीं।

मौजूदा मामले में ऐसा नहीं लगता कि मांमले के इस पहलू पर कोर्ट को ध्यान गया हो. निर्णय यह नहीं दर्शाता है कि नियमों के लिए कोई वैधानिक प्रावधान न्यायालय के समक्ष रखा गया था और अपीलकर्ता

नंबर 2 की नियुक्ति में इन वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष इस धारणा पर तर्क दिया गया है कि यदि अपीलकर्ता संख्या 2 की नियुक्ति को योग्यता के साथ असंगत दिखाया गया था जैसा कि अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा विज्ञापित किया गया था, तो वह स्वतः ही अधिकार पृच्छा की रिट जारी करने हेतु पर्याप्त है। वर्तमान कार्यवाही में, हम इस बात पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि यह धारणा अच्छी तरह से स्थापित थी या नहीं। हम अपीलों को इस आधार पर निपटाने का प्रस्ताव करते हैं कि उच्च न्यायालय के पास अपीलकर्ता संख्या 2 की नियुक्ति को रद्द करने का विकल्प हो सकता है. भले ही यह दिखाया गया हो कि प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित योग्यताओं में से एक या दूसरी योग्यता को पूर्ण नहीं किया है।

जिस कठिनाई का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, उसे महसूस करते हुए, प्रतिवादी के लिए श्री एस. यह तर्क देने के लिए कि उन्होंने उच्च न्यायालय में वैधानिक नियमों और अध्यादेशों का उल्लेख किया था, लेकिन, दुर्भाग्य से, फैसले में इसका उल्लेख या चर्चा नहीं की गई थी। हमने वर्तमान कार्यवाही में दोनों पक्षों द्वारा दायर हलफनामों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि किसी भी स्तर पर प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष यह

आग्रह नहीं किया गया है कि अपीलकर्ता की नियुक्ति में कोई त्रुटि नहीं है। 2 इस तथ्य से आगे बढ़े कि अपीलकर्ता संख्या द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों और अध्यादेशों का उल्लंघन किया गया था। प्रतिवादी द्वारा अपनी याचिका के समर्थन में दायर किए गए हलफनामे में केवल अपीलकर्ता नंबर 2 की नियुक्ति को अवैध बताया गया है, और महत्वपूर्ण रूप से यह भी जोड़ा गया है। विश्वविद्यालय की प्रतिवादी को नियुक्त करने में असफलता व अपीलकर्ता संख्या-2 की नियुक्ति निर्धारित योग्यताओं के सामने अवैध थे, और संदर्भ में ये योग्यताएं निस्संदेह अधिसूचना में प्रकाशित योग्यताओं को संदर्भित करती थी जिनके द्वारा प्रासंगिक पद का विज्ञापन किया गया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता संख्या 1 की ओर से दायर किए गए हलफनामों में से एक में मैसूर विश्वविद्यालय अधिनियम (1956 की संख्या 23) के तहत बनाए गए नियमों का संदर्भ दिया गया था, और यह जोड़ा गया था कि प्रश्नगत रीडर के पद पर नियुक्ति विश्चविद्यालय ग्रांट की धारा 26 (1) (ई) के अन्तर्गत निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार की जानी थी। जिस पर विपक्षी द्वारा विवाद किया था, और इस संबंध में, उन्होंने अस्पष्ट तरीके से आरोप लगाया कि अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा की गई सभी नियुक्तियाँ मैसूर विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत बनाए गए अध्यादेशों और नियमों द्वारा विनियमित थी। फिर उन्होंने आरोप लगाया

कि 19 अगस्त, 1959 को हुई बैठक में सीनेट द्वारा इस संबंध में बनाए गए अध्यादेशो को चांसलर ने 22 जनवरी, 1960 को अपने पत्र में मंजूरी दे दी थी।

इन आरोपों के बाद जबकि उच्च न्यायालय में इन अध्यादेशों को पेश करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था और ना ही यह दर्शाया गया कि वह कब लागू हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा धारा के तहत बनाये गये वैधानिक नियम 26 (1) को 22 जनवरी 1960 को कुलाधिपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, परन्तु वे राजपत्र में कब प्रकाशित हुए, यह हमें आज भी ज्ञात नहीं है। इसी प्रकार बनाये गये अध्यादेशों को कुलाधिपति ने उसी दिन मंजूरी दे दी थी, लेकिन वे कब लागू हुए, यह हमें नहीं पता। इस प्रकार बनाए गए और अनुमोदित वैधानिक नियम, मैसूर राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू होते हैं, और अध्यादेश ऐसी तारीख से लागू होते हैं, जैसा कि चांसलर निर्देशित कर सकते हैं (मैसूर विश्वविद्यालय की धारा 42(5) के तहत) 1956 का अधिनियम संख्या 2311 इसलिए, हालांकि अध्यादेशों का कुछ संदर्भ दिया गया था, यह दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि अध्यादेश कब लागू हुए और ऐसा प्रतीत होता है कि उस संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया है। वर्तमान कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय एक विस्तृत निर्णय है और हमें लगता है कि यह मान लेना वैध होगा कि यह वैधानिक नियमों

और अध्यादेशों का उल्लेख नहीं करता है. इसका सीधा सा कारण यह है कि न तो पक्ष ने उन पर भरोसा किया और न ही उच्च न्यायालय ने इसलिए उनकी जांच करने का कोई अवसर नहीं है। किसी भी मामले में, हमें नहीं लगता कि प्रतिवादी के लिए वैधानिक नियमों और अध्यादेशों के प्रभाव के बारे में कोई भी आधार प्रथम बार अपील में लिया जाना खुला होगा-

याचिका, जिसे उन्होंने मूल रूप से दायर किया था, जब उनके द्वारा दिए गए हलफनामे के साथ पढ़ा जाता है, तो इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है और स्पष्ट रूप से दिखाता है मेर कि उन्होंने अपीलकर्ता नंबर 2 की नियुक्ति की वैधता के खिलाफ अपने हमले को केवल इस आधार तक सीमित रखा कि अपीलकर्ता नंबर 2 ने ऐसा किया था। उन अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते जिनके द्वारा अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा आवेदन मांगे गए थे। यही वह आधार है जिस पर उच्च न्यायालय ने इस मामले को निपटाया है और यही वह आधार है जिस पर हम निपटने का प्रस्ताव करते हैं इसके साथ।

आइए हम इन अपीलों में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों की योग्यता की जांच करने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा 'दर्ज किए गए निष्कर्षों को संक्षेप में बताएं। इस संबंध में निर्धारित चार योग्यताओं का स्मरण करना आवश्यक है। अधिसूचना द्वारा अंतिम प्रश्न जो कन्नड़ भाषा

के ज्ञान से संबंधित है, उस पर विवाद नहीं है और उसे विचार से बाहर रखा जा सकता है। पहली योग्यता यह है कि आवेदक के पास किसी भारतीय विश्वविद्यालय से प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री या संबंधित विषय में किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता संख्या 2 ने अपनी मास्टर डिग्री परीक्षा में 502 प्रतिशत अंक प्राप्त किये। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा यह आग्रह किया गया था कि जब द्वितीय श्रेणी हासिल करने के लिए 50 प्रतिशत न्यूनतम आवश्यक है, तो यह सुझाव देना बेकार होगा कि 50.2 प्रतिशत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ने उच्च द्वितीय श्रेणी मास्टर डिग्री हासिल की है। और इसलिए प्रतिवादी ने दलील दी कि पहली शर्त अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा पूरी नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को बरकरार रखा है।

दूसरी योग्यता के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता संख्या 2 ने डरहम विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। उच्च न्यायालय ने माना है कि इस योग्यता के संबंध में, यदि बोर्ड ने यह विचार किया कि अपीलकर्ता संख्या 2 उस योग्यता को पूरा करता है, तो न्यायालय के लिए उस राय से भिन्न होना उचित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने योग्यता संख्या 2 के संबंध में प्रतिवादी के पक्ष में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। तीसरी योग्यता के संबंध में, ऐसा प्रतीत होता

है कि मामले पर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबी बहस हुई है। दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये गये तथा प्रतिवादी ने गम्भीरता से विवाद किया। दोनों अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया दावा कि अपीलकर्ता संख्या 2 शिक्षण के पांच साल के डिग्री कक्षाऔ के शिक्षण के अनुभव की कसौटी पर खरा उतरा।

हाई कोर्ट ने इन सबूतों की जांच की और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यद्यपि इस बिंदु पर अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री असंतोषजनक थी, लेकिन यह 'प्रतिवादी के पक्ष में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सका। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता नंबर 1 के आचरण की कड़ी आलोचना की है जिसका उल्लेख हम बाद में करेंगे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने काफी हद तक अपीलकर्ता संख्या 2 की नियुक्ति को इस आधार पर रद्द करने का निर्णय लिया कि यह स्पष्ट था कि वह पहली योग्यता को पूरा नहीं करता था। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने भी बोर्ड द्वारा बनाई गई रिपोर्ट की आलोचना की है और कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड के सदस्यों ने उस प्रश्न पर अपना दिमाग नहीं लगाया जिस पर विचार करने के लिए उन्हें बुलाया गया था।

हमारी राय में, इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि अपीलकर्ता संख्या 2 पहली योग्यता को पूरा नहीं करता है. उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से त्रुटि

में है। फैसले से पता चलता है कि. विद्वान न्यायाधीशों ने इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्च द्वितीय श्रेणी की डिग्री प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता है, और यदि प्रासंगिक प्रश्न को केवल मामले के इस पहलू के संदर्भ में निर्धारित किया जाना था, तो निष्कर्ष उच्च न्यायालय निन्दा से परे होता। लेकिन उच्च न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने में असफल रहा कि पहली योग्यता में दो भाग होते हैं - पहला भाग है: एक भारतीय विश्वविद्यालय की 'उच्च द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री, और दूसरा भाग है: इसके समकक्ष जो एक समकक्ष योग्यता है एक विदेशी विश्वविद्यालय का. ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या उच्च न्यायालय के लिए बोर्ड की राय से अलग होना उचित होगा, जबकि इसकी पूरी संभावना है कि बोर्ड ने यह विचार किया होगा कि मास्टर की डिग्री डरहम विश्वविद्यालय की कला की डिग्री, जिसे अपीलकर्ता नंबर 2 ने प्राप्त किया था, एक भारतीय विश्वविद्यालय की 'उच्च द्वितीय श्रेणी मास्टर डिग्री के बराबर थी। प्रश्न का यह पहलू पूरी तरह से एक अकादमिक मामले से संबंधित है और न्यायालय स्वाभाविक रूप से एक निश्चित राय व्यक्त करने में संकोच करेंगे, खासकर, जब ऐसा प्रतीत होता है कि विशेषज्ञों का बोर्ड संतुष्ट था कि अपीलकर्ता नंबर 2 ने पहली योग्यता पूरी की है। यदि केवल उच्च न्यायालय का ध्यान पहली योग्यता में प्रस्तुत "समकक्ष" की ओर आकर्षित किया गया होता, तो हमें

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह नहीं माना जाता कि बोर्ड ने राय व्यक्त करने में मनमाने ढंग से काम किया है।

अपीलकर्ता नंबर 2 पहली योग्यता सहित सभी योग्यताओं को पूरा करता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि हालांकि उच्च न्यायालय को दो शेष योग्यताओं के बारे में कुछ कठिनाई महसूस हुई, उच्च न्यायालय ने किसी निश्चित निष्कर्ष पर अपना निर्णय नहीं छोड़ा है कि ये योग्यताएं भी संतुष्ट नहीं थीं। पहली योग्यता पढ़ने पर स्थिति बहुत सरल प्रतीत होती है; लेकिन दुर्भाग्य से, सीएल द्वारा निर्दिष्ट समकक्ष योग्यता के बाद से। (ए) स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था, वह मामले के उस पहलू को ध्यान में रखने में विफल रहा है। मामले के उस पहलू पर यह हो सकता है कि अपीलकर्ता नंबर 2 द्वारा प्राप्त डरहम विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री पहली योग्यता और यहां तक कि दूसरी योग्यता को भी पूरा करेगी। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता संख्या 2 के पास अपने प्रकाशित कार्यों का श्रेय है जो स्वयं दूसरी योग्यता को पूरा करेंगे। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती कर रहा था कि चूंकि अपीलकर्ता नंबर 2 के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने किसी भारतीय विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री हासिल की है, इसलिए वह पहली योग्यता को पूरा नहीं करता है। यह स्पष्ट है।

कि डरहम विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री, जिसे अपीलकर्ता नंबर 2 ने प्राप्त किया है, बोर्ड द्वारा किसी भारतीय विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी मास्टर डिग्री के बराबर माना जा सकता है और लिया जाना चाहिए, और इसका मतलब है कि पहली योग्यता है अपीलकर्ता संख्या 2 से संतुष्ट। ऐसा होने पर, हमें यह मानना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता संख्या 2 की नियुक्ति को रद्द करते हुए अधिकार पृच्छा की रिट जारी कर अपीलकर्ता की नियुक्ती रद्द करने में गलती की है।

हालाँकि, इन अपीलों से अलग होने से पहले, दो अन्य मामलों का संदर्भ दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत मामले से निपटने में, उच्च न्यायालय ने बोर्ड' द्वारा बनाई गई रिपोर्ट की आलोचना की है और देखा है कि रिपोर्ट द्वारा बताई गई परिस्थितियों ने उच्च न्यायालय के लिए विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करना मुश्किल बना दिया है। हम ऐसे शैक्षणिक मामलों में उच्च न्यायालय की आलोचना का कोई मतलब नहीं समझ पाते। नियुक्ति बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा नामांकित होते हैं और जब उनके द्वारा की गई सिफ़ारिशों और उनके आधार पर नियुक्तियों को अदालतों के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो आम तौर पर अदालतों को विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए।

यहां विशेषज्ञ जिन्होंने वर्तमान बोर्ड का गठन किया है के खिलाफ बदनीयती का कोई आरोप नहीं है और इसलिए, हम सोचते हैं, अदालतों के लिए शैक्षणिक मामलों के निर्णयों को उन विशेषज्ञों पर छोड़ना आम तौर पर बुद्धिमानी और सुरक्षित होगा जो आम तौर पर अदालतों की तुलना में उन समस्याओं से अधिक परिचित होते हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। बोर्ड द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई आलोचना से यह पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने सोचा था कि बोर्ड एक कार्यकारी प्राधिकारी की स्थिति में था, एक कार्यकारी आदेश जारी कर रहा था, या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण की तरह निर्णय ले रहा था। विवादों को इसके निर्णयों के लिए संदर्भित किया जाता है। विश्वविद्यालयों जैसे शैक्षणिक निकायों द्वारा की गई नियुक्तियों के संबंध में नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों से निपटने में, ऐसा दृष्टिकोण उचित व सही नहीं होगा। वास्तव में, रिट जारी करते समय उच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं जो दर्शाती हैं कि उच्च न्यायालय ने ऐसे परीक्षण लागू किए जो वैध रूप से सर्टिओरीरी की रिट के मामले में लागू होंगे।

फैसले में यह देखा गया कि इस मामले में त्रुटि एक प्रत्यक्ष त्रुटि है। यह एक ऐसा विचार है जो उत्प्रेषण रिट की प्रक्रिया में अधिक सार्थक और प्रासंगिक है। उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि क्या चांसलर द्वारा की गई नियुक्ति ने किसी वैधानिक या बाध्यकारी

नियम या अध्यादेश का उल्लंघन किया है, और ऐसा करने में, उच्च न्यायालय को बोर्ड द्वारा व्यक्त की गई राय और उसकी तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहा है कि जब बोर्ड ने संबंधित आवेदकों के दावों पर विचार किया, तो उसने उनकी बहुत सावधानी से जांच की और वास्तव में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनमें से कोई भी प्रोफेसर नियुक्त होने के योग्य नहीं है। बोर्ड द्वारा की गई ये सिफारिशें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि उन्होंने प्रासंगिक कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रीडर के पद के लिए अपीलकर्ता नंबर 2 की सिफारिश की जानी चाहिए। इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा बोर्ड और उसके विचार-विमर्श के खिलाफ की गई आलोचना उचित नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय भी अपीलकर्ता संख्या 1 और उसके अधिकारियों के आचरण से असंतुष्ट था, और वास्तव में, अपीलकर्ता संख्या 2 के शिक्षण अनुभव की अवधि के बारे में प्रश्न से निपटते समय, उच्च न्यायालय ने देखा कि " रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री स्पष्ट प्रवृत्ति की विशेषता वाली न्यायाय को गुमराह करने के लिए संदिग्ध प्रकृति की है अगर एेसे करने का वास्तविक प्रयास नहीं।

विद्वान अटॉर्नी जनरल ने शिकायत की है कि यह आलोचना उचित नहीं है। वास्तव में, निर्णय सुनाए जाने के बाद, उन्हीं विद्वान न्यायाधीशों

को एक आवेदन दिया गया था अपीलकर्ता नंबर 1 के खिलाफ की गई आलोचना को हटा दें, और इस आवेदन के समर्थन में, श्री एथिराजुलु नायडू, जो उस समय महाधिवक्ता थे और जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष मामले पूर बहस की थी, ने एक हलफनामा दिया व दर्शाया की अपीलकर्ता नंबर 1 पर उच्च न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास का आरोप नहीं लगाया जा सकता। फिर भी, उच्च न्यायालय पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था, और इसलिए बाद में उक्त टिप्पणियों को रद्द करने के लिए किए गए आवेदन पर दिए गए फैसले में, विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि वे थे विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिए गए आश्वासन को स्वीकार करने को तैयार थे और उन्होंने स्वीकार किया कि न्यायालय को गुमराह करने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया था। फिर भी, उन्होंने माना कि न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री में गुमराह करने की प्रवृत्ति हो सकती है या होती है, और यह वह राय है जो उन्होंने विद्वान महाधिवक्ता को सुनने के बाद भी सोचा था, किसी भी दर पर अच्छी तरह से स्थापित थी, अनुचित नहीं थी।

यह आलोचना उच्च न्यायालय द्वारा की गई है क्योंकि जब अपीलकर्ता संख्या 1 के राजपत्रित सहायक श्री थिमाराजू द्वारा उसके समक्ष एक हलफनामा दायर किया गया था व अपीलकर्ता संख्या-2 के सेवा रजिस्टर का ही एक स्टेटमेंट दिनांक जून 1, 1961 का पेश किया गया।

जिसके अनुसार अपीलकर्ता संख्या 2 के पास तीसरी योग्यता द्वारा निर्धारित पांच साल से अधिक का शिक्षण अनुभव था। रजिस्टर को तब उच्च न्यायालय द्वारा भेजा गया था और जांच की गई थी, और यह स्पष्ट हो गया कि जबकि अभिसाक्षी द्वारा दायर बयान में पहली चार प्रविष्टियां उक्त रजिस्टर द्वारा वहन की गई थीं, बाद की आठ प्रविष्टियां उस रजिस्टर में दिखाई नहीं दीं। बाद में जब उच्च न्यायालय का रुख किया गया तो फैसला सुनाए जाने के बाद टिप्पणियों को हटाने के लिए एक और दस्तावेज पेश किया गया। इसे राजपत्रित अधिकारियों का रजिस्टर माना जाता है, और थिम्माराजू द्वारा दायर उद्धरण में शामिल बयान उस रजिस्टर में दिखाई दिए। अपीलकर्ता संख्या 1 और विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह था कि जब अपीलकर्ता संख्या 2 एक अराजपत्रित नौकर था, तो उसका सेवा रजिस्टर अलग से रखा गया था, लेकिन सरकारी राजपत्रित सेवकों के संबंध में, एक सामान्य सेवा रजिस्टर और सभी विवरण जो मिस्टर थिम्माराजू द्वारा पेश किए गए थे

वास्तव में अपीलकर्ता संख्या 2 के अलग सेवा रजिस्टर से लिए गए तथ्य शामिल थे, जब वह एक अराजपत्रित सेवक थे, और उनके राजपत्रित सेवक बनने के बाद सरकारी राजपत्रित सेवक रजिस्टर से लिए गए तथ्य शामिल थे। यह निस्संदेह सच कि बयान में बताए सच है कि थिम्माराजू

द्वारा दायर बयान से ऐसा प्रतीत होता है और गए सभी तथ्य अपीलकर्ता नंबर 2 के सेवा रजिस्टर से एकत्र किए गए थे, अतः एेसे कथनों पर उच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणियां उचित थी। लेकिन इस सवाल पर विचार करते समय कि क्या थिम्माराजू या अपीलकर्ता नंबर। जिसकी ओर से उन्होंने हलफनामा दिया था, ने अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया या इरादा किया, अन्य प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अपीलकर्ता संख्या 2 के शिक्षण कैरियर की लंबाई के बारे में प्रश्न पर अपीलकर्ता संख्या 2 ने 22 जुलाई, 1961 को एक विस्तृत हलफनामा दिया था। इस शपथ पत्र में, उन्होंने अपने द्वारा किए गए कई शिक्षण कार्यों और जिन अवधियों के दौरान उन्होंने उन्हें धारण किया, और ये स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि निर्धारित चरित्र का उनका शिक्षण अनुभव पाँच वर्षों से कहीं अधिक है जो कि निर्धारित न्यूनतम है। यह उल्लेखनीय है कि हालांकि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता नंबर 2 द्वारा दायर हलफनामे पर प्रत्युत्तर देने का दावा किया है, अपीलकर्ता नंबर 2 द्वारा अपने शिक्षण अनुभव के संबंध में दिए गए विवरण को प्रतिवादी द्वारा विशेष रूप से या स्पष्ट रूप से नहीं देखा गया है। इसके अलावा, यह महत्वपूर्ण है कि सरकारी राजपत्रित अधिकारियों का रजिस्टर, जो बाद में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, थिमराजू द्वारा दायर बयान में तथ्यों को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। इसलिए, एक बात स्पष्ट है कि अपीलकर्ता नंबर 2 के शिक्षण अनुभव की लंबाई के बारे में भौतिक तथ्य पूरी तरह से अपीलकर्ता

नंबर 2 के हलफनामे और यहां तक कि बाद में उत्पादित राजपत्रित अधिकारियों के रजिस्टर द्वारा स्थापित किया गया है, और इसलिए, यह हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता संख्या 1 पर इतना सख्त होने की आवश्यकता नहीं थी जब उसने पाया कि अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत सामग्री में न्यायालय को गुमराह करने की प्रवृत्ति थी, यदि ऐसा करने का वास्तविक प्रयास नहीं था। यह निस्संदेह सच है कि थिम्माराजू को रिकॉर्ड को अधिक ध्यान से देखना चाहिए था और स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि उनके द्वारा दायर क्यान में बताए गए तथ्य आंशिक रूप से अपीलकर्ता नंबर 2 के व्यक्तिगत सेवा रजिस्टर से और आंशिक रूप से रजिस्टर से लिए गए थे।

जिसे राज्य में राजपत्रित सेवकों के लिए एक सामान्य रजिस्टर के रूप में रखा जाता है। इसलिए, हमें लगता है कि विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए तर्क में कुछ दम है कि अपीलकर्ता नंबर 1 के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई कठोर आलोचना पूरी तरह से उचित नहीं है।

परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को पूरे जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाता है, दोनों अपीलकर्ताओं द्वारा दायर दोनों अपीलों में सुनवाई शुल्क का एक सेट होगा।

अपील की अनुमति.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंशुल शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।